



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 27 फरवरी, 2004/8 फाल्गुन, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 27 फरवरी, 2004

संख्या वि० स०-लैज-अनु० प्र०/1-11/2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 (2004 का

विधेयक संख्यांक-1) जो आज दिनांक 27 फरवरी, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

(जे० आर० गाजटा),
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय प्रतिरिक्त धनराशियों के मंदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2004 है ।

संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अधिक धनराशियों जिनका योग 1,94,59,61,010 रूपए (एक सौ चरानवें करोड़, उन्नसठ लाख, इकसठ हजार दस रूपए) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं, जिनका वित्तीय वर्ष 2003-2004 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों से सम्बन्धित प्रभागों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए 1,94,59,61,010 रूपए की और राशि जारी करना ।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सदा और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धनराशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में प्रामाणिक सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और विनियोजन किया जाएगा ।

विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

1 मांग संख्या	2 सेवाएं और प्रयोजन	3 निम्नलिखित राशियों से अनुधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपए	रुपए	रुपए
1	विधान सभा (राजस्व)	30,40,000	5,15,000	35,55,000
	(पूँजी)	95,00,000	—	95,00,000
2	राज्यपाल और मन्त्री परिषद् (राजस्व)	61,50,000	10,80,000	72,30,000
3	न्याय प्रशासन और (राजस्व)	5,17,68,000	73,71,000	5,91,39,000
	निर्वाचन			
4	सामान्य प्रशासन (राजस्व)	2,41,28,000	—	2,41,28,000
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन (राजस्व)	3,56,81,000	—	3,56,81,000
	(पूँजी)	1,50,00,000	—	1,50,00,000
6	श्रावकारी और कराधान (राजस्व)	47,92,000	—	47,92,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन (राजस्व)	9,41,46,825	2,30,643	9,43,77,468
8	शिक्षा (राजस्व)	15,49,15,000	—	15,49,15,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (पूँजी)	1,00,00,000	—	1,00,00,000
10	लोक निर्माण — भवन (राजस्व)	1,57,86,000	—	1,57,86,000
11	कृषि (राजस्व)	3,04,87,000	—	3,04,87,000
12	उद्यान (राजस्व)	6,30,55,000	—	6,30,55,000
13	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण (राजस्व)	4,00,000	—	4,00,000
	(पूँजी)	—	9,62,069	9,62,069
14	पशु पालन, दुग्ध विकास एवं (पूँजी)	—	77,558	77,558
	मत्स्य			
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र (राजस्व)	5,69,11,000	—	5,69,11,000
	(पूँजी)	3,57,18,000	—	3,57,18,000
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	2,000	—	2,000
	(पूँजी)	20,93,000	—	20,93,000
17	सड़कें और पुल (राजस्व)	4,14,000	14,82,862	18,96,862
18	श्रापृति, उद्योग और खनिज (राजस्व)	4,57,93,000	—	4,57,93,000
19	सामाजिक न्याय एवं (राजस्व)	4,30,82,926	—	4,30,82,926
	अधिकारिता			
20	ग्रामीण विकास (राजस्व)	4,38,63,000	—	4,38,63,000
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व)	61,27,000	—	61,27,000
	(पूँजी)	1,00,00,000	—	1,00,00,000
24	मुद्रण और लेखन सामग्री (राजस्व)	3,06,000	—	3,06,000
26	पर्यटन और नागर विमानन (राजस्व)	14,00,000	—	14,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण (राजस्व)	1,30,595	—	1,30,595
28	जलापूर्ति, नफाई, आवास (राजस्व)	8,13,41,000	—	8,13,41,000
	और नगर विकास (पूँजी)	50,12,32,000	83,58,000	50,95,90,000

2		3		
वित्त	(राजस्व)	रुपए	रुपए	रुपए
	(पूँजी)	40,20,000	7,000	40,27,000
विविध सामान्य सेवाएँ	(राजस्व)	—	43,40,48,532	43,40 48,532
	(पूँजी)	5,23,63,000	—	5,23,63,000
जनजातीय विकास	(राजस्व)	54,69,000	—	54,69,000
	(पूँजी)	2,70,02,000	—	2,70,02,000
		5,57,12,000	—	5,57,12,000
कुल जोड़		1,49,18,28,346	45,41,32,664	1,94,59,61,010
	(राजस्व)	84,71,04,346	1,06,86,505	85,77,90,851
	(पूँजी)	64,47,24,000	44,34,46,159	1,08,81,70,159

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अशेषित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

दिनांक 27 फरवरी, 2004.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें [क्षिप्त विभाग, नस्ति संख्या फिन-ए-सी (2)-19/2003]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2004

31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उन का विनियोग करने के लिए विधेयक ।

बोरभद्र सिंह,
मुख्य मंत्री ।

जे० एल० गुप्ता,
सचिव (विधि) ।

शिमला :
दिनांक 27 फरवरी, 2004.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 1 of 2004

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A
BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31st day of March, 2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth year of the Republic of India, as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation Act, 2004.

Issue of a further sum of Rs. 1,94,59,61,010 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 2003-2004.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 1,94,59,61,010 (one hundred and ninety four crore, fifty nine lakh and sixty one thousand and ten rupees only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2003-2004 in respect of the services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 De- mand No.	2 Services and purposes		3 Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Conso- lidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Vidhan Sabha (Revenue)		30,40,000	5,15,000	35,55,000
	(Capital)		95,00,000	—	95,00,000
2	Governor and Council of Ministers (Revenue)		61,50,000	10,80,000	72,30,000
3	Administration of Justice and Election (Revenue)		5,17,68,000	73,71,000	5,91,39,000
4	General Administration (Revenue)		2,41,28,000	—	2,41,28,000
5	Land Revenue and District Administration (Revenue)		3,56,81,000	—	3,56,81,000
	(Capital)		1,50,00,000	—	1,50,00,000
6	Excise and Taxation (Revenue)		47,92,000	—	47,92,000
7	Police and Allied Organisations (Revenue)		9,41,46,825	2,30,643	9,43,77,468
8	Education (Revenue)		15,49,15,000	—	15,49,15,000
9	Health and Family Welfare (Capital)		1,00,00,000	—	1,00,00,000
10	Public Works—Building (Revenue)		1,57,86,000	—	1,57,86,000
11	Agriculture (Revenue)		3,04,87,000	—	3,04,87,000
12	Horticulture (Revenue)		6,30,55,000	—	6,30,55,000
13	Irrigation and Flood Control (Revenue)		4,00,000	—	4,00,000
	(Capital)		—	9,62,069	9,62,069
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries (Capital)		—	77,558	77,558
15	Planning and Backward Area Sub-Plan (Revenue)		5,69,11,000	—	5,69,11,000
	(Capital)		3,57,18,000	—	3,57,18,000
16	Forest and Wild Life (Revenue)		2,000	—	2,000
	(Capital)		20,93,000	—	20,93,000
17	Roads and Bridges (Revenue)		4,14,000	14,82,862	18,96,862
18	Supplies, Industries and Minerals (Revenue)		4,57,93,000	—	4,57,93,000
19	Social Justice and Empowerment (Revenue)		4,30,82,926	—	4,30,82,926

1	2		3		
			Rs.	Rs.	Rs.
20	Rural Development	(Revenue)	4,38,63,000	—	4,38,63,000
23	Water and Power Development	(Revenue)	61,27,000	—	61,27,000
		(Capital)	1,00,00,000	—	1,00,00,000
24	Printing and Stationery	(Revenue)	3,06,000	—	3,06,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue)	14,00,000	—	14,00,000
27	Labour, Employment and Training	(Revenue)	1,30,595	—	1,30,595
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	8,13,41,000	—	8,13,41,000
		(Capital)	50,12,32,000	83,58,000	50,95,90,000
29	Finance	(Revenue)	40,20,000	7,000	40,27,000
		(Capital)	—	43,40,48,532	43,40,48,532
30	Miscellaneous General Services	(Revenue)	5,23,63,000	—	5,23,63,000
		(Capital)	54,69,000	—	54,69,000
31	Tribal Development	(Revenue)	2,70,02,000	—	2,70,02,000
		(Capital)	5,57,12,000	—	5,57,12,000
	Grand Total		1,49,18,28,346	45,41,32,664	1,94,59,61,010
	(Revenue)		84,71,04,346	1,06,86,505	85,77,90,851
	(Capital)		64,47,24,000	44,34,46,159	1,08,81,70,159

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 2003-2004.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The 27th February, 2004.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A.C. (2)19/2003]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation Bill, 2004 recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION BILL, 2004

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on 31st day of March, 2004.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J. L. GUPTA,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The 27th February, 20004.